the stand taken by the managements of the banks.

The policy of the Government is always to sort out the issues raised by the employees through mutual discussions. It was in this spirit that agreements were reached on pension and computerisation in the banking industry at a huge cost of Rs. 500 crores annually.

Increase in Power Supply to Andhra Pradesh

*717. DR ALLADI P. RAJKUMAR: Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) whether Government hae any plans to increase power supply to Andhra Pradesh;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether Government have plans to increase finance to Ramagudam Thermal Power Station; and

(d) what is the present quantum?

THE MINISTER OF POWER (SHRI N.K.P. SALVE): (a) and (b) Government's plan to increase power supply to Andhra Pradesh is as under :—

(i) Allocation for Andhra Pradesh from the unallocated output of the Central Sector Stations in the Southern region has been enhanced from 25 per cent to 50 per cent w.e.f. 1-3-1994.

(ii) Assistance from Western Region is being provided to Andhra Pradesh.

(iii) A capacity addition of 1303.6 MW has been targetted during 8th Plan period for Andhra Pradesh.

The other measures taken to increase the power supply to the State of Andhra Pradesh include maximising of generation from existing units, reduction in T&D losses, implementation of better demand management and energy conservation measures etc.

(c) and (d) At present capacity of NTPC Ramagundam Theremal Power Station is 2100 MW. Presently there is no proposal to increase capacity requiring additional finance at this station. Future proposals however include installation of additional 500 MW capacity at NTPC Ramagundam STPS and installation of 2 Units of 250 MW each at APSEB's Ramagundam TPS Extension.

सरकारी क्षेत्र के बैंकों की घाटे में चल रही शाखाएं

*718. प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : श्रीमती सुषमा स्वराज

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में सरकारी क्षेत्र के विभिन्न बैंकों की ऐसी 104 शाखाओं की पहचान की है जो निरन्तर घाटे में चल रही है;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों में ऐसी शाखाओं की राज्य-वार संख्या कितनी है तथा ये कहां-कहां स्थित हैं;

(ग) इनमें कुल कितने कर्मचारी कार्यरत हैं ;

(घ) क्या सरकार इन बैंक शाखाओं का भविष्य में कार्य संचालन करने हेतु कोई स्पष्ट नीति अपना रही है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(च) इन शाखाओं को हर वर्ष औसत कुल कितनी राशि का घाटा हो रहा है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) वर्ष 1992-93 के दौरान हानि उठाने वाली 28 सरकारी क्षेत्र के बैंकों की शाखाओं की कुल संख्या 13232 थी। माननीय संसद सदस्यों ने जिन 104 शाखाओं का जिक्र किया है वे राष्ट्रीयकृत बैंकों की वे शाखाएं हैं जिन्हें बैंकों द्वारा दिसम्बर 1993 में भारतीय रिजर्व बैंकों को प्रस्तुत किए गए समझौता ज्ञापन में बंद करने या उनका विलय करने/के लिये पता लगाया गया है।

जिन शाखाओं को बंद करने/उनका विलय करने के लिये पता लगाया गया है उनका बैंक-वार ब्यौरा क्या है नीचे दिया गया है :—

बैंक का नाम	शाखाओं की संख्या
1. आन्ध्रा बैंक	8
2. बैंक आफ इंडिया	10
3. बैंक आफ महाराष्ट्र	10
4. सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	10
5. इंडियन ओवरसीज बैंक	10
6. सिंडिकेट बैंक	11
7. युनाइटेड बैंक आफ इंडिया	25
8. यूको बैंक	20
	104

इस बारे में राज्य-वार सूचना और इन शाखाओं में कार्य कर रहे कर्मचारियों की कुल संख्या तत्काल उपलब्ध नहीं है लेकिन इसे एकत्र किया जा रहा है और उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा ।

(घ) और (ङ) सरकार को यह आशा है कि निष्क्रिय परिसंपत्तियों की निरंतर वसूली, बेहतर ऋण प्रबंधन और परिचालनात्मक व्यय में कटौती करने की नीति अपनाकर शाखा स्तर पर परिचालन को लाभ प्रद बनाया जाना चाहिए । जहां तक संभव है सरकार की यह नीति है कि हानि उठाने वाली शाखाओं के वित्तीय कार्यनिष्पादन में सुधार किया जाये, ताकि ये अर्थक्षम हो जाएं ।

(च) इन शाखाओं को वार्षिक रूप से हो रही हानि की कुल राशि से संबंधित सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध तथा नियमों के अंतर्गत अनुज्ञेय सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

Shortfall in the Power Targets of Eighth Five Year Plan

*719. DR. NAUNIHAL SINGH: Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there is going to be a heavy shortfall in the target in the power sector of the Eighth Five Year Plan;

(b) if so, how much, and what are the reasons therefor;

(c) whether there is going to be a peaking shortage;

(d) if so, how much;

(e) what was the growing demand for power every year, the details thereof;

(f) what are the details of steps which Goernment have taken to cope up with the above mentioned problem?

THE MINISTER OF POWER (SHRI N. K. P. SALVE): (a) and (b) The capacity addition target fixed for 8th Plan is 30537. MW. However, about 20000 MW of new generation capacity may be added during the Plan period. In addition to funds constraints, the other main reasons for shortfall are delay in land acquisition, law and order problems and the requirement of strict compliance with environment, regulations, etc.

(c) and (d) Based on the new capacity addition of about 20000 MW the anticipated peaking power shortages in the terminal year of the 8th Five Year Plan (1996-97) is around 28 per cent.

(e) The demand of power for the various years of the 8th Plan is indicated below :—

Year	Peak Demand (MW)	Energy Requirement (MKwh)
1992-93 (Actual)	52,805	305,266
1993-94 (Actual)	54,875	323,252
1994-95 (Anticipated)	58,000	345,640
1995-96 (Estimated as per 14th Electric Power Survey)	68,541	386,970
1996-97	73,656	416,274